SarkariExam.Com

अपडेट सबसे पहले

अब घंटो पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र कुछ मिनटों मे ही लीजिये General Knowledge की जानकारी – और रहिए अपडेट ॥ अब से हर रोज SSC MTS और Exam के लिए के General Knowledge के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपडेट हम आपको देंगे, जो करेंगे मदद आपके सभी Exams मे और आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच ॥

Special 15 Questions for General Knowledge

18/03/2020

10. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है—

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1919

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1909

(d) भारत सरकार अधिनियम, 1947

U.P. P.C.S. (Mains) 2008

उत्तर—(b)

11. केंद्रीय विधानसभा का/के निम्नांकित में से कौन-सा/से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ/हुए?

(A) 1926

(B) 1937

(C) 1945

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए :

कूट :

(a) केवल (A) (b) (B) और (C)

(c) (A) और (C) (d) (A), (B) और (C)

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018

उत्तर–(c)

वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ था।

12. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 'संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत' प्रवृत्त किया गया?

(a) 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम

(b) 1919 का भारत सरकार अधिनियम

(c) 1935 का भारत सरकार अधिनियम

(d) 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

M.P.P.C.S. (Pre) 2017

उत्तर–(c)

संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी।

13. भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है?

(a) मार्ले-मिंटो सुधार, 1909

(b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935

(d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

I.A.S (Pre) 2012

उत्तर—(c)

---

14. निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी—

(a) इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था।

(b) अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे।

(c) यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था।

(d) इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

उत्तर—(b)

15. एक 'संघीय व्यवस्था' और 'केंद्र' में 'द्वैध शासन' भारत में लागू किया गया था—

(a) 1909 के अधिनियम द्वारा (b) 1919 के अधिनियम द्वारा

(c) 1935 के अधिनियम द्वारा (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

उत्तर—(c)

---

16. अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था—

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में

(b) अगस्त प्रस्ताव, 1940 में

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919 में

(d) कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 1946 में

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

उत्तर—(a)

18. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं?

(a) संघीय विधानपालिका को (b) प्रांतीय विधानमंडल को

(c) गवर्नर जनरल को (d) प्रांतीय गवर्नरों को

U. P. P. C. S. (Mains) 2008

I.A.S. (Pre) 2018

उत्तर—(c)

19. निम्नांकित में से कौन-सा एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?

(a) देश के लिए लिखित संविधान

(b) विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि

(c) एक संघ की योजना पर विचार

(d) विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित (nominate) किया जाना

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

उत्तर—(a)

भारत शासन अधिनियम, 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम, 1935 में समाहित थे।

20. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

(a) यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है

(b) इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली

(c) इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है

(d) इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

उत्तर–(a)

भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं–1. संघात्मक सरकार की स्थापना, 2. केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, 3. प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, 4. द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, 5. प्रांतीय शासन व्यवस्था, 6. प्रांतीय विधानमंडल, 7. केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा 8. फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि।